so. He told me that one of the members was a doctor who was working in a hospital in Ludhiana. So he travelled all the way to Ludhiana. It is not only harassment; it also interferes with transparency and impartiality. As I said, we are also repeatedly requesting the State Governments. In fact, the Government of Uttar Pradesh has already abolished interview for teachers. We now have interviews only for such assignments where certain skill is required. But there also the skill test is only a qualifying test. So it does not actually interfere. So we are trying to cut down on the room for nepotism or also room for any other considerations by way of interview. This is one step. I would like to add that beginning from this year, in fact, from the 25th of December, which we observed as a Good Governance Day, marking the birthday of Shri Atal Bihari Vajpayee, we have initiated the process of simplifying the application forms. Sir, you would agree with me that we have voluminous forms, repetitive information. On every fifth page they ask you 's/o' (son of), as if every fifth page the father changes, it is so ridiculous. I myself have got into this exercise. We have prepared a form. We began with a pensioner form. For example, for pension, what is required? You require the name of the pensioner, the date of birth of the pensioner, the date of retirement, the last pay-scale on which the pension has to be decided the nominee from the family to whom the pension should go in case the pensioner doesn't live tomorrow and fifth may be bank account. You don't require how many times he has married or not married, etc. So, we are trying to cut down and simplify it because that would not only add to ease, but also add to transparency and impartiality.

Public Sector Undertakings identified as sick

†*20. DR. SANJAY SINH: Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the number of Public Sector Undertakings identified as sick;

(b) whether Government has any plan to revive them, if so, the time-frame fixed therefor;

(c) whether the revival process will be carried out on priority basis; and

(d) the number of such undertakings identified for revival in Assam and Uttar Pradesh?

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ANANT GEETE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the information available in Public Enterprises Survey 2013-14, that was laid on the Table of Both Houses of Parliament on 26.2.2015, there are 65 sick Central Public Sector Enterprises (CPSEs) as on 31.3.2014.

† Original notice of the question was received in Hindi.

(b) to (d) The responsibility of addressing the sickness of Central Public Sector Enterprises (CPSEs), including those located in Assam and Uttar Pradesh lies with the concerned administrative ministries/departments. The administrative Ministries/ Departments monitor the sickness of CPSEs functioning under their control and take timely redressal measures for revival/ restructuring/disinvestment of sick/loss making CPSEs with the approval of the competent authority.

Department of Public Enterprises has issued on 29.10.2015 guidelines for "Streamlining the mechanism for revival and restructuring of sick/incipient sick and weak Central Public Sector Enterprises: General principles and mechanism of restructuring" to be followed by the administrative Ministries /Departments for revival/restructuring or closure of CPSEs under their administrative control in a time bound manner.

The concerned administrative Ministries/Departments would identify sick CPSEs functioning under them, formulate revival/restructuring plan for such CPSEs on a case-to-case basis and after obtaining the approval of competent authority implement the plan.

डा. संजय सिंहः माननीय सभापति, इस प्रश्न पर आपका संरक्षण चाहिए। इसमें बड़ा स्पष्ट सवाल किया गया है कि कितने भारी उद्योग रुग्ण हैं? उसका जवाब आ गया है कि मार्च, 2014 तक 65 यूनिट रुग्ण थे। उसी में दूसरे सप्लीमेंटरी में भी सवाल किया गया था। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 65 यूनिट रुग्ण हैं, अगर सरकार की मंशा है उनको रुग्णता से बाहर निकालने की, तो उसकी योजना क्या है और उसमी समय-सीमा क्या है?

श्री अनंत गीतेः सभापति जी, आज जो 65 लोक उद्यम बीमार हैं, वे अलग-अलग भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के तहत हैं। मेरा मंत्रालय बी.पी.ई. द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सदन के समक्ष जब भी कोई प्रश्न आता है तो वह जानकारी सदन के समक्ष रखते हैं। मेरे मंत्रालय के तहत, भारी उद्योग विभाग, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, उनमें 12 उद्योग हैं तो प्रॉफिट में चल रहे हैं, 19 उद्योग हैं, जो बीमार हैं। ये उद्योग कई वर्षों से बीमार हैं। ये आज बीमार नहीं हैं, ये उद्योग 2007 से धीरे-धीरे बीमार होते गए। जब से हमने इस विभाग का पद भार संभाला है, मैंने निर्णय किया कि जो बीमार उद्योग हैं, जिनकी जीरो प्रोडक्टिविटी है और जहां कोई काम नहीं चलता है तथा सेलेरी चल रही है, प्रमोशन चल रहे हैं और सरकार के हजारों-करोड़ रुपए बरबाद हो रहे हैं, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि जो उद्योग बीमार हैं तथा बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते, उनको बंद करना ही आवश्यक है। तो ऐसे 5 उद्योग हैं जिनका हमने चयन किया और उनको बंद किया। इनमें HMT Chinar, HMT bearings, HMT watches, Tungabhadra steel, Hindustan Cable Corporation हैं। तो जो उद्योग बीमार हैं, जो चल नहीं सकते, उनको बंद करने का हमने निर्णय किया है। जिनका रिवाइवल हो सकता है, ऐसे तीन-चार उद्योग जो मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उनके रिवाइवल का हम प्रयास कर रहे हैं।

डा. संजय सिंहः माननीय सभापति जी, मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश और असम में दोनों राज्यों की विषम परिस्थिति है। वैसे असम तो इकॉनोमिक फ्रंट पर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ऊपर गया है, लेकिन अगर वहां के उद्यमों की मदद करके आगे बढ़ा दिया जाए या जीवित कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि असम और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट्स का बड़ा कल्याण होगा। उसके बारे में क्या मंत्री जी कुछ प्रकाश डालेंगे?

श्री अनंत गीतेः महोदय, सदस्य का जो सवाल है वह हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ

है। असम का, Cachar का, आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, वह देकर हम इस cachar के HPC के रिवाइवल करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री संजय राउतः सर, 65 सिक पब्लिक सैक्टर उद्यमों के बारे में मंत्रालय ने जानकारी दी है। इसमें से बहुत सी बीमार हैं और बीमारी से बाहर नहीं आ सकी हैं। लेकिन मेरी जानकारी में कुछ ऐसे भी उद्योग हैं, जो भारी मंत्रालय ने उनकी योजना बनाई थी, उनकी घोषणाएं की थी और अब तक उनका प्रपोजल आगे नहीं बढ़ सका। उनमें से एक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अमेठी में पेपर उद्योग का रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में आपके मंत्रालय के तहत जो पेपर इंडस्ट्री बनाने का एक प्रोजेक्ट था, उसका स्टेट्स क्या है? क्या यह प्रोजेक्ट आगे जा रहा है? अगर आगे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है और वह कहां बनेगा?

श्री अनंत गीतेः सभापति जी, माननीय सदस्य संजय राउत जी ने जगदीशपुर पेपर मिल के बारे में प्रश्न किया है। वैसे यूपीए-I, और यूपीए-II, ये दोनों सरकारों के समय यानी 2007 में जगदीशपुर पेपर मिल को कैबिनेट ने सैंक्शन किया, 2014 में सरकार के जाते-जाते भी फिर एक बार कैबिनेट ने उसे पारित किया, लेकिन दुर्भाग्य से जो जमीन का मामला है, वह उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है। जो जमीन उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मिलनी थी, वह जमीन उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दे नहीं पाई। जो दूसरी जमीन है, वह एक ट्रस्ट की है। वह ट्रस्ट न्यायालय में गया हुआ है और मामला न्यायालय में लंबित पड़ा है। इसीलिए 2007 से आज हम 2016 में हैं, लेकिन हम उस जगदीशपुर पेपर मिल को शुरू नहीं कर पाए। जब कोर्ट का यह मामला सुलझ जाएगा, तब उसके बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री संजय राउतः सर, मेरा प्रश्न है कि ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No supplementary on supplementary. Now, Dr. Bhalchandra Mungekar.

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: Sir, with all regards to the hon. Minister, the reply given to all four sub-questions is, absolutely, evasive. There is no clear-cut answer. My supplementary is this. Out of these 65 sick industries, if five are to be closed down, then, out of the remaining 60 sick industries, how does the Ministry classify as to what their degree of sickness is and what kind of revival is necessary? I ask this because the answer which the Minister has given just now is that the Ministry is collecting the information. The Heavy Industry Ministry is not a data collecting centre. It is a Ministry which is supposed to monitor the policy. Therefore, the questions are: What concrete policy is there in order to address the question of sickness, what kind of sickness is there and what kind of revival plan are they having?

श्री अनंत गीतेः सभापति जी, मेरे पास दो विभाग हैं - एक भारी उद्योग है और दूसरा लोक उद्यम यानी Department of Public Enterprises है। यह जो सवाल है, वह Department of Public Enterprises से रिलेटेड है और इस विभाग का काम information collect करना है तथा information collect करते हुए जो concerned Departments and Ministries हैं, उनको सलाह देना है। इस प्रकार की सलाह Department of Public Enterprises द्वारा, जो 65 सिक यूनिट्स हैं, उन सारी concerned Ministries को दी गई है। अब निर्णय उन मंत्रालयों को करना है। जहां तक Department of Heavy Industries का संबंध है, उसकी जानकारी मैंने पहले प्रश्न में दी है।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, definitely, I don't like to embarrass the hon. Minister by raising questions on the sick PSUs pertaining to other Ministries, which are not under his wing. But I will have to point out to him that the condition of these 65 sick units has been carried on in the Department of Public Enterprises' survey for, at least, more than a decade. It is a matter of indifference of the successive Governments and, still, we are talking about 'Make in India'. Closing down HMT and, at the same time, chanting 'Make in India' doesn't match because the Hindustan Machine Tools (HMT) had been the backbone of our industrial society. Now, my point is, we have been pursuing, at every stage, almost every month, the issue of Tyre Corporation of India. This is under your Ministry. For the last three years, the workers have not been getting salary. You may wait for 17 years for Ahmedabad Paper Mill, but the workers are not receiving salary, people are retiring without their PF, gratuity and other terminal dues! There are a number of contract workers who have to survive on that public sector industry, whose number is more than the regular workers, who are just starving. What will be your perspective plan? You may wait for 17 years, पर उसके घर में तो चूल्हा भी नहीं जलेगा, तो कम से कम question your Department, which ones are not identified for revival. There must be a time-bound action. Which is not revivable as per BRPSE?

MR. CHAIRMAN: Put your question please.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: On Tyre Corporation of India, BRPSE has concluded its observations. You are also talking about mines, but since three years they have not got their wages. On Hindustan Cables Corporation, I don't know whether there is a tug of war between the Ministry of Defence and your Ministry going on. I don't know whether they will take over and revive it. I don't know what the situation is , but workers are in the same limbo till now. Have you got any time-bound plan? I am not talking about your 'Make in India' etc. But they are poor individual workers. At least tell them, 'Okay, this is the final pay.' Don't delay it. I think this is one of your own mandates, of your Ministry.

श्री अनंत गीतेः सभापति जी, सदस्य तपन सेन जी ने कर्मचारियों की जो चिन्ता यहां पर जताई है, उससे मैं सहमत हूं। उन्होंने यहां पर टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कही है। दुर्भाग्य से टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिस पर कोर्ट ने provisional liquidator appoint किया है, उसके कारण अब हम उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। चूंकि वह मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने उसमें provisional liquidator appoint किया हुआ है, इसी वजह से पिछले कई महीनों से हम उनका वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने हिन्दुस्तान केबल की बात कही है। हमने हिन्दुस्तान केबल का निर्णय किया है। सभापति जी, मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि हमने जितने भी यूनिट्स बन्द करने के निर्णय किए हैं, उन सभी का स्वागत कर्मचारियों ने किया है। उन्होंने उसका स्वागत इसलिए किया है कि जो कर्मचारी वर्ष 1987 के पे-स्केल पर वहाँ नौकरी कर रहे थे, उनको हम वर्ष 2007 के पे-स्केल पर वीआरएस दे रहे हैं। इतना अच्छा पैकेज इससे पहले किसी भी सार्वजनिक लोक उद्यम को नहीं मिला था, तो सारे कर्मचारी उसका स्वागत कर रहे हैं, विरोध कहीं भी नहीं हो रहा है। यह निर्णय हमने किया है। जो उद्योग मेरे मंत्रालय के तहत आते हैं, उन सारे उद्योगों के मामले में हमने यह निर्णय किया है। केबल कॉर्पोरेशन के बारे में भी अंतिम निर्णय हो चुका है और लगभग एक महीने के अंदर ये सारे मामले सेटल हो जाएंगे।

श्री तपन कुमार सेनः आप टायर कॉर्पोरेशन के बारे में क्या करेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री अनंत गीतेः सर, मैंने टायर कॉर्पोरेशन के बारे में जवाब दे दिया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Next question please. Shri Tapan Kumar Sen, please sit down. ...*(Interruptions)*... No; Mr. Tapan Sen, that is all. Question No. 21. ...*(Interruptions)*...

श्री तपन कुमार सेनः यह मामला कोर्ट में है, यह बोलकर क्या आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है? ...(**व्यवधान**)... Sir, he has not replied to my specific question.

MR. CHAIRMAN: All right, you can take it up with the Minister if the answer is not up to your satisfaction.

Local purchases of stationery from Kendriya Bhandar

*21. SHRI RAM KUMAR KASHYAP: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether DoPT made it incumbent on all Government departments to make all local purchases of stationery, etc. from Kendriya Bhandar in order to strengthen cooperative movement;

(b) whether Hon'ble Minister has recently lauded contribution of Kendriya Bhandar in providing various household goods and products of day-to-day use at competitive price; and

(c) if so, the reasons for not extending validity of OM No. 14/12/94-Welfare beyond 31.3.2015 and depriving Government departments of purchasing quality items at cheaper rates than in open market?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Kendriya Bhandar is a society registered under Mufti State Cooperative Societies Act, 2002. The objective of Kendriya Bhandar is to provide essential commodities and household items at competitive and fair prices to Central Government employees and others through its retail stores in and outside Delhi.

2. Department of Personnel and Administrative Reforms on 14.7.1981 made it incumbent on all Central Government Departments, their attached/subordinate offices etc. and other organization financed and/or controlled by Government located at Delhi/ New Delhi to make all local purchases of stationery and other items required by them only from the Central Government Employees Consumer Cooperative Society Ltd. (now known as Kendriya Bhandar), New Delhi.

3. Subsequently, the policy was changed and it was decided on 05.07.2007 *inter-alia* to give a special dispensation in respect of all Central Government Departments,